(b) Does not arise.

High level focus committee for modernisation and improvement of telephone services in Calcutta

*37. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the high level focus committee for modernisation and improvement of the Calcutta City Telephone Services has completed its study and submitted its report; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE ((SHRI DINESH GOSWAMI): (a) It is understood that the Committee has already completed its study. However, the final report has not yet been formally submitted to the Department.

(b) Details will be known after the Committee submits its report.

फिजी में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों की दुर्दशा

*38. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिजी की वर्तमान सरकार द्वारा वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण और अपमानजनक बर्ताव किए जाने के कारण उनका जीवन असुरक्षित और दयनीय हो गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में संबंधित सरकार से बातचीत की है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और भविष्य में सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) फिजी में जातीय भेदभाव पूर्ण, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था स्थापित करने के जो गैर-कानूनी प्रयास किए जा रहे हैं, उन पर भारत सरकार को चिन्ता है और उनसे भारतीय, मूल के फिजी नागरिकों के राजनैतिक आर्थिक और नागरिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) भारत सरकार फिजी की असंवैधानिक "अन्तरिम सरकार" को मान्यता नहीं देती । दो सैन्य विद्रोहों के फलस्वरूप स्थापित हुई "अन्तरिम सरकार" की स्पष्ट भेदभावपूर्ण और राजनैतिक दृष्टि से प्रतिगामी कार्यवाहियों की उसने साफ शब्दों में निन्दा की है । हमने इस मामले को उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बराबर उठाया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्र मण्डल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच तथा अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय विचार-विनिमय भी शामिल है । सरकार फिजी में जातीय भेद-भाव को संस्थागत रूप देने के प्रयासों का बराबर विरोध करती रहेगी और इनके साथ ही न्यायोचित और न्यायसंगत संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना के लिए किए जाने वाले शांतिपूर्ण प्रयासों की प्रोत्साहन देती रहेगी क्योंकि सिर्फ इन्हीं से वहां शांति, स्थायित्व और जातीय समरसता का सुनिश्चिय हो सकता है । फिजी के समाज के सभी वर्गों में निष्ठापूर्ण बातचीत ही एक ऐसा संभव तरीका है जिससे कि सभी फिजीवासियों के अधिकारों का सुनिश्चिय हो सकता है जिसमें भारत मूल के लोग भी शामिल हैं ।